साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 30 अगस्त 2021, वर्ष-7, अंक-22

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

» मध्यप्रदेश के 2612 गांवों में मोबाइल और लैंडलाइन कनेक्टिविटी नहीं

» दूरसंचार कनेक्टिविटी से सिंगरौली के 97 और सीधी के 83 गांव आज भी वंचित

» रीवा सांसद के सवाल पर लोकसभा में उपलब्ध आंकड़ों में हुआ खुलासा

» मप्र का उज्जैन एकमात्र जिला जिसके सभी गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी

आजादी के 75 साल बाद भी मध्यप्रदेश के ढाई हजार गांव 'आउट ऑफ नेटवर्क'

अरविंद मिश्र, भोपाल

कहते हैं भारत गांवों में बसता है। लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि आज जब हम आजादी 75वीं वर्षगांठ का देशभर में जश्न मना रहे हैं। वहीं मप्र के ढाई हजार गांव आज भी 'आउट ऑफ नेटवर्क' हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में गांवों की संख्या 51,527 है। यानी की मध्य प्रदेश में कुल 51,527 गांव हैं। ये गांव मध्य प्रदेश के 52 जिलों के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित सभी 52 जिलों को पुनः अनुमंडल, तालुका इत्यादि में बांटा गया है। गांव विकास का राग अलापने वाले जनप्रतिनिधियों के दावों की पोल हाल ही में संसद में पेश एक रिपोर्ट ने खोलकर रख दी है।

इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि आज के समय में मोबाइल कनेक्टिविटी में मध्यप्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े 10 जिले हैं। संचार सेवाओं में फिसड्डी जिलों में बैतूल, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, बालाघाट, मंडला, सिंगरौली, पन्ना, सिवनी, सीधी और होशंगाबाद शामिल हैं। यहां सबसे खास बात यह है कि आउट ऑफ नेटवर्क दस जिलों में पांच जिले आदिवासी बाहूल हैं। वहीं उज्जैन प्रदेश का एकमात्र जिला है जिसके सभी 1095 गांव टेलीफोन कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। इसके बाद झाबुआ, दतिया और भिंड बेहतर स्थिति में हैं जिनके सिर्फ 3-3 गांव ही मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित हैं।

दूरसंचार कनेक्टिविटी से सिंगरौली के 97 और सीधी जिले के 83 गांव आज भी वंचित हैं। यहां मेरे द्वारा कुछ सरकारी टॉवर लगवाने के प्रयास किए गए हैं। जिसमें मुझे काफी हद तक सफलता भी मिली है। अगर अभी भी कुछ गांव संचार सेवाओं से वंचित हैं तो उनकी सूची निकलवाकर वहां भी टॉवर लगवाने के प्रयास करूंगी।

रीति पाठक, सांसद, सीधी

रीवा सांसद ने खोली पोल

सूचना क्रांति के दौर में जब तमाम सरकारी सेवाएं इंटरनेट व टेलीकम्युनिकेशन के भरोसे हैं, ऐसे में मप्र के 2612 गांव में यह सेवा शुरू भी नहीं हुई है। इन गावों में न तो मोबाइल नेटवर्क पहुंचते हैं, न ही लैंडलाइन टेलीफोन सर्विस है। मौजूदा दौर में यह बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन हकीकत यही है। रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा द्वारा लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में इसी माह चार अगस्त को केंद्रीय संचार मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है।

49317 गांव ही मोबाइल नेटवर्क

मप्र में वर्तमान में 51 हजार 929 आबाद गांव हैं। जिनमें प्रदेश के 72 प्रतिशत आबादी रहती है। लेकिन 49317 गांव ही मोबाइल और लैंडलाइन दूरसंचार कनेक्टिविटी है। 2612 गांव दूरसंचार कनेक्टिविटी से वंचित हैं। वंचित गांवों को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की विभिन्न योजनाओं के तहत चरणबद्ध तरीके से कवर किया जा रहा है। वंचित गांवों से में मप्र के 228 गांवों को अभी तक यूएओएफ की मौजूदा योजनाओं में कवर कर लिया गया है।

भोपाल के 13 गांवों में कनेक्टिविटी नहीं

भोपाल जिले में कुल 501 गांव हैं, जिनमें से 13 गांवों में दूरसंचार कनेक्टिविटी का अभाव है। सभी गांव बैरसिया तहसील के हैं। वहीं इंदौर जिले में कुल 614 गांव हैं, जिनमें से 8 गांवों में अभी तक टेलीफोन कनेक्टिविटी नहीं है। ग्वालियर जिले में 1264 आबाद गांव हैं, जिनमें 59 में कनेक्टिविटी नहीं हैं। वहीं जबलपुर में कुल 1377 गांव हैं जिनमें 20 में कनेक्टिविटी का अभाव है।

सर्वाधिक पिछड़े 10 जिले

जिला	छूटे गांव
बैतूल	210
छिंदवाड़ा	183
डिंडोरी	176
बालाघाट	125
मंडला	115
सिंगरौली	97
पन्ना	92
सिवनी	89
सीधी	83
होशंगाबाद	81

इनका कहना है

दूरसंचार कनेक्टिविटी से बालाघाट के 125 गांव वंचित हैं। इसकी जानकारी प्रशासन को है। प्रशासन पूरे प्रयास से जुटा है कि वंचित गांवों में संचार सुविधाएं मुहैया हों।

उमा महेश्वरी, सीईओ, जिला पंचायत, बालाघाट

» मप्र को जरूरत 40 लाख टन की, मिल रही 23 लाख टन

» खाद के लिए विपणन विभाग के गोदाम का चक्कर काट रहे

» डिंडोरी में पुलिस के साए में किसानों को दी जा रही खाद

प्रदेश में खाद की किल्लत

भोपाल। प्रदेश के कई जिलों में रासायनिक खाद की किल्लत शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा कमी विदिशा, बैतूल, सतना, डबरा, बालाघाट और डिंडोरी जिले में है। यहां सहकारी समितियों में खाद का पूरा स्टॉक खत्म हो चुका है। समितियां और किसान खाद के आने का इंतजार कर रहे हैं। अभी प्रदेश में करीब एक लाख टन खाद का स्टॉक है। खाद की नियमित आपूर्ति के लिए सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव ने केंद्रीय रसायनिक एवं उर्वरक विभाग के सचिव से मिलकर चर्चा भी की है। प्रदेश में जिस तरह से खेती का रकबा बढ़ा है, उसके हिसाब से 40 लाख टन खाद की जरूरत किसानों को है, लेकिन सिर्फ 258 लाख टन खाद ही मिल पा रही है। पिछले खरीफ सीजन में किसानों को दस लाख टन खाद मिली थी, लेकिन इस वर्ष सिर्फ आठ लाख टन ही खाद मिल पाई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा यूरिया की खपत है। यहां दस लाख टन अकेले यूरिया की सप्लाई होती है।

डिंडोरी में खाद नहीं मिलने पर हंगामा

इधर, डिंडौरी जिले में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों ने एक बार फिर पुरानी डिंडोरी मंडला बस स्टैंड स्थित खाद गोदाम में जमकर हंगामा किया। देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया की पुलिस के पहरे में किसानों को खाद बांटना पड़ा। गोदाम के सामने खाद लेने के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को शांत कराया। इसके बाद किसानों को खाद दिलाने में सहयोग भी किया।

कालाबाजारी

खाद की कमी के चलते अब उसकी कालाबाजारी शुरू हो गई है। इसमें सबसे ज्यादा उन किसानों को परेशानी होती है, जो डिफॉल्टर हो गए हैं। उन्हें समितियां खाद देने से हाथ खड़े कर देती हैं। ऐसे में वे साहूकारों के माध्यम से खुले बाजार से औने-पौने दामों में खाद खरीदते हैं। सहकारिता विभाग के अधिकारियों के अनुसार खाद की रैक एक-दो दिन में आने की संभावना है।

इनका कहना है

मध्यप्रदेश में किसानों और गरीबों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम किसानों के कल्याण और विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। किसान भाई चिंतित न हों। डिंडोरी ही नहीं, कहीं भी यूरिया की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। डिंडोरी में यूरिया भेजने का कार्य जारी है। विगत 2 दिनों में 128 मैट्रिक टन यूरिया पहुंच चुका है। 150 मैट्रिक टन और पहुंच जाएगा।

कमल पटेल, कृषि मंत्री

मप्र के किसानों को मिलेगी 16 हजार सम्मान निधि!

» खुशखबरीः पीएम किसान का पैसा हो सकता है दोगुना

» किसानों के खाते में 2000 की जगह आएंगे 4000 रुपए

विशेष संवाददाता, भोपाल

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ पाने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। बहुत जल्द किसानों के खाते में 2000 रुपए की जगह 4000 रुपए की किस्त आने वाली है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जल्द लाभार्थी किसानों को यह तोहफा दे सकती है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को डबल करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को हर साल 6000 रुपए की जगह 12000 रुपए तीन किश्तों में मिल सकते हैं। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र के इस निर्णय से सबसे ज्यादा मप्र के किसान लाभान्वित होंगे। चूंकि मप्र के किसानों को कुल 16 हजार रुपए किसान सम्मान निधि के मिलेंगे। गौरतलब है कि शिवराज सरकार राज्य के किसानों को केंद्र के अलावा चार हजार रुपए दे रही है।

केंद्र में हुआ मंथन

बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को दोगुना करने पर भी चर्चा की गई है। हालांकि, अभी इस पर कोई फैसला अभी नहीं किया गया है।

2019 में शुरू हुई थी योजना

मोदी सरकार ने 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरू की थी। इस योजना के तहत सरकार छोटे किसानों को हर साल 6000 रुपए तीन किस्तों में देती है। पहली किस्त एक दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है। दूसरी किस्त एक अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त एक अगस्त से 30 नवंबर तक किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है।

मंडियों की आमदनी बढ़ाने के लिए मंडी बोर्ड ने बनाया प्लान

मंडियां होंगी आत्मनिर्भर! खाली जमीन पर लगेंगे कृषि उद्योग

प्रशासनिक संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश की 'सी' और 'डी' ग्रेड की मंडियों की आय बढ़ाने के लिए मंडी बोर्ड ने पहल की है। एग्रीकल्चर इंफास्ट्रक्चर फंड के तहत मध्यप्रदेश की सी और डी वर्ग की मंडियां जिनकी आय और आवक बहुत कम है वो खुद के रखरखाव का खर्च नहीं उठा पाती हैं। ऐसी मंडियों की खाली पड़ी जमीन को कृषि आधारित उद्योगों को आवंटन करने की योजना है। इससे वहां कई तरह के कृषि से जुड़े प्लेटफॉर्म बन सकेंगे और रखरखाव से लेकर और कई बेहतर सुविधाएं विकसित हो सकती हैं। एग्रीकल्चर इंफास्ट्रक्चर फंड स्कीम के तहत 'सी' ग्रेड की 56 और 'डी' ग्रेड की 122 मंडियों की खाली जमीन पर कृषि आधारित उद्योगों को भूमि आवंटन करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। ताकि मंडियां आत्मनिभर हो सकें।

मिलेंगी कई बेहतर सुविधाएं

कृषि आधारित उद्योगों के तहत वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, असेइंग लैब, इलेक्ट्रानिक तौल कांटा, सार्टिंग ग्रेडिंग प्लांट, ड्राइंग यार्ड, ट्रेडिंग प्लेटफार्म, रायपेनिंग चेंबर्स, प्रायमरी कलेक्शन सेंटर, इरेडिशन प्लांट्स, दाल, चावल, आटा तेल मिलों के साथ-साथ सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट आदि प्लांट्स स्थापित किए जाने की प्लानिंग की जा रही है।

जमीन के चयन का काम शुरू

इधर, बताया ता रहा है कि मंडी बोर्ड के सातों संभागों (भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा) के तहत आने वाली 'सी' और 'डी' वर्ग की मंडियों की जमीन को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है।

लैंड बैंक बना रहा मंडी बोर्ड

मंडी बोर्ड एक लैंड बैंक बना रहा है, जिससे ये पता चल सके कि किस मंडी के पास कितनी जमीन इस्तेमाल के लिए खाली है। इस काम के लिए 10 सितंबर 2021 तक का टारगेट रखा गया है। ये जमीन प्राइवेट इंवेस्टर को उपयोग के लिए एक तय समय के लिए आवंटित की जा सकेगी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कुल 269 मंडियां और 298 उप मंडियां हैं। इन मंडियों में 6500 कर्मचारी कार्यरत हैं और 45,000 रजिस्टर्ड कारोबारी हैं। मंडी बोर्ड इन कारोबारियों से 1.5 फीसदी टैक्स लेकर 0.5 फीसदी राज्य सरकार को देता है।

इनका कहना है

मंडी बोर्ड के सातों संभागों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा की 'सी' और 'डी' वर्ग की मंडियों की भूमि का चिन्हांकन का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस संबंध में 24 अगस्त को मंडी बोर्ड मुख्यालय में बैठक कर प्राइवेट इन्वेस्टर को मंडियों में उपलब्ध रिक्त भूमि आवंटन करने के संबंध में कार्य योजना बनाई गयी है।

प्रियंका दास, प्रबंध संचालक
मंडी बोर्ड, मप्र भोपाल

खरगोन में स्थपित होंगे 53 नए उद्योग, किसानों की बढ़ेगी आय

प्रशासन का दावाः पांच हजार स्थानीय युवकों को मिलेगा रोजगार

संवाददाता, खरगोन

कलेक्टर अनुग्रह पी की अध्यक्षता में कलेक्टर सभाकक्ष में एक अहम बैठक आयोजित की गई। जिसके बाद जिले में करोड़ों रुपए का निवेश तो होगा ही इससे जिले के स्थानीय युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध होंगे। इसके अलावा किसानों की आर्थिक स्थिति में भी निश्चित रूप से सुधार होगा। एक जिला एक उत्पाद और जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन समिति एवं नियति संवर्धन समिति की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला उद्योग प्रबंधक एसएस मंडलोई ने बताया कि यहां मिर्च, प्याज और बेसन सहित अन्य खाद्य प्रसंस्करण के लिए टैमला में 10 हेक्टेयर भूमि का चयन किया जा चुका है। यहां खाद्य प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने वाले इच्छुक उद्यमियों को भी चयन कर लिया गया है। जो अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित खाद्य प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करेंगे। इनके द्वारा यहां 50 करोड़ रुपए का निवेश होगा। बैठक में कृषि उपसंचालक एमएल चौहान, उद्यानिकी उपसंचालक एम मुजाल्दे, कृषि वैज्ञानिक एसके त्यागी, नाबार्ड के विजेन्द्र पाटील, एफपीओ प्रबंधक किशोर माली उपस्थित रहे।

कॉटन उद्योग में 800 करोड़ का होगा निवेश

मंडलोई ने बताया कि वर्तमान में जिले में 100 जीन और 8 स्पीनिंग मिले हैं। जिसमें 3 फ्रेबिक वाले उद्योग जिले में है। वहीं 2 उद्योगों द्वारा कॉटन आधारित उत्पाद बनाने के लिए 800 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। ये उद्योग नवीन ईकाई विस्तार होगा। इसमें 5 हजार युवकों को रोजगार मिल सकता है। वहीं 53 नए उद्योग स्थपित होंगे। जो 2422 करोड़ का नवीन पूंजी निवेश करेगी। इसमें 10 हजार युवकों को रोजगार उपलब्ध होगा। इसके अलावा जिले में 15 मिर्च प्रोसेसिंग इकाई स्थापित है। अभी 1 टेमला में और 7 निमरानी में शुरू होने वाला है।

मिर्च के लिए एफपीओ तैयार

बैठक में उद्यानिकी उपसंचालक एम मुजाल्दे ने बताया कि सुरपाला में निमाड़ीलाल के नाम से मिर्च के लिए एक एफपीओ बनाया गया है। इसका लायसेंस भी बना दिया गया है। इस एफपीओ में 27 एफआईजी जिसमें 540 सदस्य जुड़ चुके हैं। इसी तरह कॉटन के लिए भी एक एफपीओ बनाया गया है। इसमें 18 आईजी और 360 सदस्य जुड़े हैं। जो अगले सीजन में व्यवस्थित रूप से कार्य शुरू करेंगे। इसके अलावा चार आवेदकों द्वारा मिर्च आधारित इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन किया गया। ये चारों आवेदन 35 लाख रुपए की लागत वाले उद्योग स्थापित करेंगे। विभाग द्वारा 10 लाख अनुदान भी दिया जाएगा।

मप्र के व्यापारियों को मंडी आईकॉन के रूप में किया जाएगा सम्मानित

मप्र-राजस्थान की मंडियों के बीच होगा अंतर्राज्यीय व्यापार

संवाददाता, भोपाल

भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा ई-नेम ऑनलाईन ट्रेडिंग पोर्टल पर इन्टरस्टेट ऑनलाईन मंडी व्यापार बढ़ाने की पहल की जा रही है। इस संबंध में मंडी बोर्ड की प्रबंध संचालक प्रियंका दास द्वारा गत दिवस राजस्थान एवं मध्यप्रदेश राज्य की मंडी समितियों के मध्य अंतर्राज्यीय व्यापार किए जाने के संबंध में दोनों राज्यों की सीमावर्ती कृषि मंडियों के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं व्यापारियों की संयुक्त रूप से आनलाइन वर्चुअल मीट आयोजित की गई। वर्चुअल मीट में संगीता ढोके संयुक्त संचालक (ई-नेम), मंडी बोर्ड के आंचलिक कार्यालय के संयुक्त/उप संचालक, राजस्थान मंडी बोर्ड की ओर से सोहनलाल शर्मा, निदेशक, राजस्थान कृषि विपणन निदेशालय, केशर सिंह, संयुक्त संचालक, उदयपुर एवं कोटा खंड के उपसंचालक, मप्र की मंदसौर, नीमच, जावरा, मंडी के सचिव और व्यापारी, रतलाम, डबरा, दतिया, मुरैना, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, बैतूल, इंदौर, धार, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, कुक्षी, गंधवानी, एवं रीवा मंडी सचिवों के साथ राजस्थान राज्य की कोटा, रामगंज मंडी, निम्बाहेड़ा, चोमेला, भीलवाड़ा, भवानी मंडी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, फतेहनगर, करोली, झालावाड़ा, मंडी के सचिव एवं व्यापारी मौजद रहे।

व्यापारियों ने दी सहमति

बैठक में मंडी बोर्ड भोपाल एवं राजस्थान मंडी बोर्ड के अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश और राजस्थान राज्यों में प्रचलित अनुज्ञप्ति/विपणन संबंधी प्रावधानों/प्रक्रियाओं के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। जिससे उपस्थित व्यापारियों ने ई-नेम पोर्टल पर इंटरस्टेट मंडी व्यापार बढ़ाए जाने के लिए सहमति दी।

प्रशिक्षण के निर्देश

मंडी बोर्ड की प्रबंध संचालक प्रियंका दास द्वारा ई-नेम पोर्टल पर इंटरस्टेट व्यापार करने वाले मप्र के व्यापारियों को मंडी आईकॉन के रूप पुरस्कृत किए जाने की बात कहते हुए मप्र तथा राजस्थान के व्यापारियों अधिकारियों तथा कर्मचारियों को एक-दूसरे के राज्य में जाकर उक्त राज्यों में ई-नेम की गतिविधियों का प्रशिक्षण लेने के निर्देश दिए।

प्रदेश में सरकार किसानों से खरीदेगी बिजली

» सोलर संयंत्र लगाने पर 10 लाख खर्च आएगा

» मंत्री बोले-किसानों के जीवन में आएंगी खुशियां

प्रशासनिक संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश में पीएम कुसुम योजना में किसानों द्वारा उत्पादित बिजली ऊर्जा विभाग द्वारा खरीदी जाएगी। किसानों द्वारा सोलर संयंत्र लगाए जाने पर 10 लाख रुपए का खर्च आएगा और आमदनी 50 लाख रुपए से ज्यादा हो सकेगी। पीएम कुसुम-अ योजना में सौर ऊर्जा उत्पादकों के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा, हमारे कोयला और तेल जैसे ऊर्जा के संसाधन कम हो रहे हैं, लेकिन सूर्य देव की कृपा सबके ऊपर समान रूप से है। इसका उपयोग कर हम प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित ऊर्जा विभाग खरीदेगा, बिजली की बिक्री से जो लाभ होगा, उससे किसानों के जीवन में नई खुशियां आएंगी। तोमर ने आह्वान किया कि बिजली की बचत करें, जिससे बिजली बिल कम आए और पैसा बचे। प्रदेश की कुल विद्युत खपत की लगभग 25 प्रतिशत पूर्ति नवकरणीय ऊर्जा द्वारा हो रही है।

रीवा की ऊर्जा से चल रही दिल्ली मेट्रो

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि सोलर ऊर्जा के रूप में जो बीज आप डालोगे, वह वर्षों आपको लाभान्वित करेगा। प्लांट लगाने के लिए बैंक से लोन भी सरलता से मिलेगा। किसान अब उद्योगपति भी बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, रीवा के सोलर प्लांट से दिल्ली की मेट्रो ट्रेन चल रही है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट ओंकारेश्वर में बन रहा है। इससे 600 मेगावॉट सौर ऊर्जा मिलेगी।

निविदाकर्ता 40 किसान

भारत सरकार के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कुसुम-अ योजना के तहत प्रदेश में कुल 300 मेगावॉट क्षमता का आवंटन किया गया है। ऊर्जा विकास निगम द्वारा अब तक निविदा के दो चरणों में कुल 42 निविदाकर्ताओं का सौर ऊर्जा उत्पादक के रूप में चयन कर 75 मेगावॉट क्षमता का आवंटन किया जा चुका है। निविदाकर्ताओं में 40 किसान शामिल हैं।

इनका कहना है

मध्य प्रदेश में सरकार अब किसानों से अनाज के साथ-साथ बिजली भी खरीदेगी। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में करीब दस लाख का खर्च आएगा। इससे 25 साल तक आय होगी, जो 50 से 60 लाख होगी।

प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री

किसान अब फसल उत्पादक के साथ ही ऊर्जा उत्पादक भी बनेंगे। सूरजमुखी की तरह सूरज ऊर्जा का भी उत्पादन करेंगे। इस क्षेत्र में सभी मिलकर अन्य प्रदेशों के लिए प्रतिमान स्थापित करेंगे।

संजय दुबे, प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

तिरुपति बालाजी की 'मां वकुला' के रूप में गेहूं की नई प्रजाति का अवतार

» पूर्णा के चौदह साल बाद इंदौर के गेहूं अनुसंधान केंद्र ने तैयार की किस्म

» भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान ने नई प्रजाति को दी मंजूरी

संवाददाता, इंदौर

गेहूं उत्पादक किसानों के लिए खुशखबर है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के इंदौर स्थित क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र से नई प्रजाति का अनुसंधान हुआ है। केंद्र के कृषि विज्ञानियों ने तिरुपति बालाजी यानी भगवान वेंकटेश के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए इस नई प्रजाति को उनकी माता वकुला का नाम दिया है। इसका विज्ञानी नाम एचआई-1636 (पूसा-वकुला) रखा गया है। केंद्र से समय पर बोने वाली गेहूं की पूर्णा एचआई-1544 प्रजाति के 14 साल बाद नई प्रजाति जन्म हुआ है। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान ने इस नई प्रजाति को चिन्हित किया है। संस्थान की वेराइटल आइडेंटिफिकेशन कमेटी ने इसे मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही भारत सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना जारी होने की संभावना है। इसके बाद इसी साल इस प्रजाति का प्रजनक बीज (ब्रीडर सीड) तैयार किया जाएगा। अगले दो साल में आम किसानों तक बीज पहुंचने की उम्मीद है। यह प्रजाति भारत के मध्य क्षेत्र की जलवायु के हिसाब से अनुकूल होगी। इसलिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान के कोटा-उदयरपुर क्षेत्र के अलावा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बोई जा सकेगी।

रोटी और बिस्किट के लिए बेहतर

पूसा-वकुला में जिंक भरपूर मात्रा (44.4 पीपीएम) में है। प्रोटीन भी 12 प्रतिशत के आसपास है। यह गेहूं चपाती के लिए बेहतर होगा। बिस्किट बनाने के लिए भी यह बहुत अच्छा होगा। जिंक की अच्छी मात्रा के कारण यह कुपोषण भी दूर करेगा। इसकी औसत पैदावार 56.6 क्विंटल होगी, जबकि इसकी पैदावार की अधिकतम क्षमता 78.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आंकी गई है। दाना मोटा होगा और बोवनी का समय नवंबर में 5 से 15 तारीख के बीच तय किया गया है। इस प्रजाति को चार-पांच सिंचाई की जरूरत होगी। इसकी एक खासियत यह भी है कि तना और पत्ती के गेरुआ रोग का असर नहीं होगा।

पूसा प्रभात का भी उदय

पूसा-वकुला के साथ ही इंदौर क्षेत्रीय केंद्र ने मालवी ड्यूरम गेहूं के रूप में पूसा-प्रभात (एचआई-8823) प्रजाति भी विकसित की है। मालवी ड्यूरम गेहूं की मालव कीर्ति प्रजाति के अनुसंधान के 16 साल बाद यह नई प्रजाति लाई गई है। यह पास्ता, दलिया आदि के लिए बहुत उपयुक्त होगा। इस प्रजाति का उपयोग कच्चे माल के रूप में सेमोलिना आधारित उद्योगों में किया जा सकता है।

इनका कहना है

हमने पूसा-प्रभात प्रजाति को विकसित किया है। यह कम पानी वाली प्रजाति है। एक-दो सिंचाई में इसकी फसल पककर तैयार हो जाएगी। इसे 20 से 30 अक्टूबर के बीच मध्य क्षेत्र के राज्यों में बोया जा सकेगा। इस गेहूं में भरपूर प्रोटीन के अलावा आयरन की मात्रा 37.9 पीपीएम और जिंक 40.1 पीपीएम होगा। पूसा प्रभात की औसत पैदावार 38.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगी, जबकि इसकी पैदावार की अधिकतम क्षमता 65.6 क्विंटल तक आंकी गई है। इसका दाना मोटा है और यह गेरुआ रोग के लिए प्रतिरोधी है।

डॉ. दिव्या अंबाटी, कृषि वैज्ञानिक, इंदौर अनुसंधान केंद्र

महान स्त्रियों को सम्मान देने के लिए हमने पहले भी गेहूं की प्रजातियों के नाम उसी तरह रखे हैं। इस बार हमने भगवान श्रीकृष्ण के ही रूप तिरुपति के भगवान वेंकटेश (बालाजी) की माता वकुला के नाम पर गेहूं की नव विकसित प्रजाति एचआई-1636 का नाम रखा है। पूसा-वकुला की पैदावार पूर्णा से पांच प्रतिशत अधिक है। मध्य प्रदेश में तो इस समय 75 प्रतिशत क्षेत्र में पूर्णा ही बोया जाता है। पूर्णा की तरह यह नई प्रजाति भी प्रदेश के अलावा मध्य क्षेत्र के किसानों के लिए उपज में वरदान साबित होगी।

डॉ. एसवी साईप्रसाद, प्रमुख वैज्ञानक, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र इंदौर

खेतों में तार फेंसिंग के लिए सरकार देगी 70 फीसदी सब्सिडी

» फसलों को बचाने उद्यानिकी विभाग के प्रस्ताव पर लगी मुहर

» हर साल 40 प्रतिशत फसल तबाह कर देते हैं जंगली जानवर

भोपाल। फल, सब्जी, मसाले, फूल और औषधि की 40 प्रतिशत तक फसल को हर साल जंगली और आवारा जानवर नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा, खेतों में इनको रोकने के लिए सुरक्षा के उपाय न हो पाने के कारण हो रहा है। इसलिए अब प्रदेश सरकार का उद्यानिकी विभाग खेतों की तार फेंसिंग कराने के लिए किसानों को सहायता के तौर पर 50 से 70 प्रतिशत तक सब्सिडी देगा। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 20 ब्लॉक (विकासखंड) चिन्हित किए गए हैं। प्रोजेक्ट के अच्छे परिणाम आने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। उद्यानिकी विभाग के इस प्रस्ताव को सरकार से मंजूरी मिल गई है। अगले दो महीने में इसके लिए काम शुरू होगा।

ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य

कई किसान अधिक खर्च के कारण खेतों को सुरक्षित नहीं कर पाते जिससे उनकी फसलों को जानवर नुकसान पहुंचा देते हैं। इसे सुरक्षित करने के लिए खेतों की चेन फेंसिंग के लिए अब सरकार सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस योजना को तैयार किया था और अब इसे स्वीकृति मिल गई है। मप्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, सरकार किसानों को चेन फेंसिंग के लिए 70 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी।

- भारत सिंह कुशवाह, उद्यानिकी मंत्री मप्र शासन

प्राकृतिक संसाधनों से आत्म-निर्भर मप्र की नई तस्वीर

राजेश बैन,
अधिकारी,
जनसंपर्क, मप्र

मध्यप्रदेश के संसाधनों और कौशल से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सुनियोजित विकास की दिशा अब आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। इसी साल 8 अप्रैल को लगभग 1891 उद्यमों की शुरुआत इसकी एक बानगी है। प्रदेश में आगामी एक-दो माह में ही 3000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम शुरू किए जाने पर काम चल रहा है। मध्यप्रदेश सरकार के हाल ही में लागू औद्योगिक भूमि तथा आवंटन एवं प्रबंधन नियम-2021 ने प्रदेश में छोटे-छोटे उद्योगों को लगाने में नव-उद्यमियों के लिए नए द्वार खोले हैं।

मध्यप्रदेश के संसाधनों और कौशल से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सुनियोजित विकास की दिशा अब आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। इसी साल 8 अप्रैल को लगभग 1891 उद्यमों की शुरुआत इसकी एक बानगी है। प्रदेश में आगामी एक-दो माह में ही 3000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम शुरू किए जाने पर काम चल रहा है। मध्यप्रदेश सरकार के हाल ही में लागू औद्योगिक भूमि तथा आवंटन एवं प्रबंधन नियम-2021 ने प्रदेश में छोटे-छोटे उद्योगों को लगाने में नव-उद्यमियों के लिए नए द्वार खोले हैं। अब नव-उद्यमी औद्योगिक क्षेत्रों के अविकसित भूखंड भी ले सकेंगे और अपनी तरह से अपने उद्यम की जरूरत के हिसाब से भूखंडों का विकास और आवश्यक निर्माण कर सकेंगे। सरकार की सोच है कि नव-उद्यमी को विकसित भूखंडों में व्यय होने वाली अत्यधिक पूंजी में राहत मिले और वे इस राशि का उपयोग अपने उद्यम की मशीनरी तथा कच्चे माल आदि में कर सकें। मध्यप्रदेश ने क्लस्टर आधारित उद्योगों में बड़ी छलांग लगाई है और यह क्रम अनवरत है। मध्यप्रदेश के अकूत प्राकृतिक संसाधन और कौशल के व्यापक तथा वास्तविक उपयोग के माध्यम से रोजगार सृजन की दिशा में सतत प्रयास जारी है। मध्यप्रदेश के विभिन्न अंचलों की खासियत और कौशल के समन्वय से कलस्टर आधारित उद्यमों में बड़ा निवेश और रोजगार सम्भावित है। इंदौर में खिलौना और फर्नीचर कलस्टर, जबलपुर में टेक्सटाइल कलस्टर, सागर में नए फर्नीचर हब, बैतूल में बांस कलस्टर जैसे अनेक कलस्टर के साथ नव उद्यमी आगे आए हैं। भारत सरकार ने भी कलस्टर आधारित मध्यप्रदेश के प्रस्तावों को बड़े पैमाने पर मंजूरी दी है। इसी दिशा में भारत सरकार के क्लस्टर विकास कार्यक्रम अंतर्गत कॉमन फेसिलिटेशन सेंटर का एक प्रस्ताव एवं अधोसंरचना विकास के 11 प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं। भारत सरकार के क्लस्टर विकास कार्यक्रम अंतर्गत बैतूल जिले में गुड़ निर्माण करने वाली इकाइयों के लिए कॉमन फेसिलिटेशन सेंटर का प्रस्ताव और गुना जिले में बहुमंजिला औद्योगिक कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव भी है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग द्वारा नए विभागीय औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2021 से अब नवीन नियमों में पहली बार अविकसित शासकीय भूमि को निजी विकासकों को आवंटित करने की योजना बनाई गई है। योजना में 6 विकासकों द्वारा क्लस्टर विकसित करने पर भी भूमि का आवंटन हो सकेगा। बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर विकसित करने की भी भारत सरकाए से सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्य 7680.65 लाख रुपए के विरुद्ध 8881.80 लाख रुपए मार्जिन मनी अनुदान भी वितरित किया गया है, जो लक्ष्य का 116 प्रतिशत है। इस वर्ष अब तक 2090.44 लाख रुपए मार्जिन मनी अनुदान वितरित कर उद्योगों को संजीवनी दी गई है। विभाग ने वृहद स्तर पर प्रयास कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अप्रैल में 1891 एमएसएमई इकाइयों का एक साथ शुभारंभ करवाया था। इन 1891 इकाइयों में से 776 इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं और इनमें रुपए 1160.90 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश एवं 14 हजार 15 व्यक्तियों को रोजगार सृजित हुआ है। कोरोना काल में भी एमएसएमई विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन की सतत आपूर्ति के लिए निरंतर सहयोग प्रदान किया गया। प्रदेश में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए वर्ष 2021-22 में अब तक कुल राशि 21.74 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति विभिन्न क्रियान्वयन संस्थाओं को मंजूर की गई है। भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की योजनांतर्गत ग्वालियर में एपेरल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है। राज्य में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अपनी स्थापना के बाद से विभाग ने विभिन्न पहलों के माध्यम से एमएसएमई विकास के लिए एक अनुकूल पारिस्थिति-तंत्र स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस अवधि के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यम के क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति बनाई है। राज्य के एमएसएमई को एक आशाजनक वातावरण प्रदान करने के प्रयास और प्रतिबद्धता के कारण ही क्लस्टर विकास के लिए भारत सरकार की योजनाओ का लाभ प्रदेश को लगातार मिल रहा है। यही कारण है कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और क्षमता बढ़ाने के लिए कलस्टर का भरपूर उपयोग हो पा रहा है। प्रदेश में सामान्य सुविधा केंद्र प्रस्ताव के तहत भी सामान्य उत्पादन, प्र-संस्करण केंद्र, परीक्षण सुविधाएँ, डिजाइन केंद्र, अपशिष्ट उपचार संयंत्र, प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, कच्चा माल बैंक और बिक्री डिपो जैसी मूर्त परिसंपत्तियों को शामिल किया गया है। उत्पाद प्रदर्शन केंद्र और सूचना केंद्र स्थापना के लिए 15.31 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में बड़ी संख्या में आईडी अपग्रेडेशन सहित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (आईडी) प्रस्ताव भी स्वीकृत हुए हैं, जिसमें भूमि का विकास, जलापूर्ति का प्रावधान, जल निकासी, बिजली वितरण के लिए ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत, सड़कों का निर्माण, प्राथमिक चिकित्सा जैसी सामान्य सुविधाएं शामिल हैं। केंद्र प्रवर्तित इस स्कीम से कैंटीन, नए औद्योगिक (बहु-उत्पाद) क्षेत्रों, संपदाओं या मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों, संपदाओं के समूहों में अन्य आवश्यकता आधारित आधारभूत सुविधाएं मुहैया होंगी। फिलहाल राज्य में एमएसएमई में 69 हजार 237 पंजीयन हुए हैं और इन इकाइयों में 15,744.50 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ही 6.62 लाख रोजगार सृजित किए गए हैं। मध्यप्रदेश सरकार अपनी एमएसएमई विकास नीति के माध्यम से पात्र औद्योगिक संस्थाओं को विकास सब्सिडी और रियायत भी प्रदान करता है। विभाग ने इस अवधि के दौरान 173 करोड़ रुपए की राशि से लगभग 2000 इकाइयों को सहायता प्रदान की है।

कोविड-19 का दूसरा डोज जरूरी क्यों?

डॉ. संतोष शुक्ला

हम सभी ने विगत दो लहरों में देखा है कि कोरोना बीमारी लईलाज है। इसके खतरे इतने ज्यादा हैं कि कुछ लोग काल कवलित हो जाते हैं, जो जीवित बच जाते हैं वे किसी न किसी प्रकार की कमी से ग्रसित रहते हैं। नागरिकों के टीका न लगवाने वाले कारणों के विश्लेषण उपरांत जो बातें समक्ष आई हैं। उन्हें समझाइश के माध्यम से यह बताना जरूरी है कि टीकों के माध्यम से हमने विभिन्न बीमारियों पर विजय प्राप्त की है जैसे- पोलियो, टिटनस, स्मॉल पॉक्स इत्यादि। कोरोना महामारी से पीड़ित हेल्थकेयर वर्कर्स के समूह में किए गए शोध के अनुसार जिन नागरिकों को कोविड-19 टीके का प्रथम डोज लग चुका था उनकी एंटीबॉडी (रोग प्रतिरोधक क्षमता) लगभग 40-60 प्रतिशत एवं जिनको दोनों डोज लग चुके हैं उनकी एंटीबॉडी 93 प्रतिशत के साथ अधिक मजबूत होना पाई गई है। विश्लेषित आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के पूर्ण टीकाकरण अर्थात दोनों डोज के बाद नागरिकों में अस्पताल में भर्ती होने की दर में 95 प्रतिशत तथा संभावित मृत्यु दर में 98 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। यह आंकड़े ही बताते हैं कि जो लोग कोविड-19 टीके का प्रथम डोज प्राप्त कर द्वितीय डोज से वंचित रह गए हैं वे स्वयं जागरूक होकर आगे आएं एवं द्वितीय डोज अवश्य लगवायें। यह इसलिए भी जरूरी है कि पूर्ण टीकाकृत नागरिक ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ाई लड़ने में समक्ष रहेंगे। मात्र प्रथम डोज या जिन्होंने एक भी टीका नहीं लगवाया है। ऐसे नागरिकों को संक्रमण जल्दी पकड़ेगा और वह गंभीर भी हो सकेगा। टीके पूर्णरूपेण सुरक्षित, प्रभावित एवं हानिरहित हैं। अत: सभी नागरिक टीकों से नहीं बीमारी से डरें। समझदारी दिखाएं और कोविड-19 टीके के दोनों डोज अवश्य लगवाएं। वर्तमान में हमारे देश में शासकीय स्तर पर दो टीके दिए जा रहे हैं। पहला- कोवैक्सीन, जिसमें प्रथम डोज के बाद 28-42 दिन के अंतराल पर द्वितीय डोज तथा दूसरा- कोविशील्ड, जिसमें प्रथम डोज के बाद 84-112 दिन के अंतराल पर द्वितीय डोज दी जा सकती है। मध्यप्रदेश आज की स्थिति में कोविड-19 के टीकाकरण में देश में कई प्रदेशों से आगे बना हुआ है। प्रदेश में 16 जनवरी 2021 से संचालित कोविड-19 टीकाकरण अभियान में प्रदेश में 18 से अधिक आयुवर्ग के लक्षित 5.49 करोड़ नागरिकों के विरुद्ध 23 अगस्त 2021 तक 3.35 करोड़ कोविड-19 प्रथम डोज (61 प्रतिशत) 65.93 लाख कोविड-19 द्वितीय डोज (12 प्रतिशत) लगे हैं। हेल्थकेयर वर्कर्स 8.93 लाख, फ्रंटलाईन वर्कर्स 9.50 लाख, 18 से 45 वर्ष के 2.11 करोड़ नागरिक, 45 से 60 वर्ष के 1.11 करोड़ नागरिक, 60 से अधिक आयु के 66.88 लाख नागरिकों का कोविड-19 टीकाकरण किया जा चुका है। 25-26 अगस्त 2021 को आयोजित कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान सफल रहा। इसे सफल बनाने के लिए पहले ही समस्त तैयारियां पूरी कर ली गईं थीं। यहीं नहीं, नागरिकों की सहायता के लिए 24×7 टोल फ्री नंबर 104 एवं 1075 पर टीकाकरण तथा बीमारी संबंधित नि:शुल्क चिकित्सीय परामर्श की सेवाएं उपलब्ध कराई गई थीं। जहां टीकाकरण बीमारी से लड़ने का स्थाई साधन है, लेकिन वहीं सभी नागरिकों से निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी), मास्क (घर से घर तक), सेनेटाईजर (20 सेकेंड तक हाथ धोना) का पालन अवश्य करें।

शिल्प एवं कला से होगा आत्मनिर्भर मप्र का स्वप्न साकार

अनिल वशिष्ठ,
अधिकारी
जनसंपर्क, मप्र

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के स्वप्न को साकार बनाने में स्थानीय शिल्पकला एक मजबूत कड़ी है। परम्परागत कला को रोजगार के रूप में विकसित करके ही आत्म-निर्भरता के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के स्वप्न को साकार बनाने में स्थानीय शिल्पकला एक मजबूत कड़ी है। परम्परागत कला को रोजगार के रूप में विकसित करके ही आत्म-निर्भरता के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस मंत्र को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मसात कर लिया है। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमेप के लिए तीन दिन तक विषय विशेषज्ञों, आर्थिक नीति सलाहकारों के साथ अगस्त-2020 से विस्तृत विचार-मंथन के उपरांत उसमें स्थानीय संसाधनो का बैहतर इस्तेमाल कर स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करना,एक जिला-एक उत्पाद, लोकल फॉर वोकल जैसे आधारभूत विषय उभर कर आऐ हैं, इन पर कार्य करते हुए 2023 तक आत्म-निर्भरता में लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। इस लक्ष्य की पूर्ति में ग्रामोद्योग की महती भूमिका होगी। इस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। भारत वर्ष में शिल्पकला की अक्षुण परम्परा रही है। ईसा से 2500 वर्ष पूर्व हड़प्पा एवं सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत और अब आत्म-निर्भर भारत से आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश तक शिल्पकला की यह परम्परा निरंतर जारी है। समृद्ध भारत में शिल्पकारों की कला की खनक को पूरी दुनिया सदैव से महसूस करती आ रही है। कोरोना काल ने स्थानीय बाजार, स्थानीय उत्पाद के महत्व को सिद्ध कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्म-निर्भर भारत से लेकर आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के स्वप्न को साकार बनाने में ग्रामीण भारत अहम भूमिका अदा कर रहा है। ग्रामीण और शहरी अंचल में रहने वाले स्थानीय शिल्पी परम्परागत शिल्प तैयार कर अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हो रहे हैं। यही शिल्प उनकी रोजी-रोटी का जरिया बना है। इनके उत्पादों को बाजार मुहैया कराने के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करने का काम राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। चंदेरी और महेश्वर के शिल्पियों ने अपने सधे हुए हाथों से करघों में ऐसा ताना-बना बुना कि, पूरी दुनिया उनकी कला की दीवानी हो गई है। सूती और रेशमी धागे से तैयार साड़ियां, सलवार-सूट, बरबस ही अपना ध्यान खींच लेती हैं। इसी तरह धार जिले में बाघ की ब्लॉक प्रिंट ने भी अपनी अलग पहचान बनाई है। धार जिले के धरा प्रिंट सेंटर में माण्डू क्षेत्र की आदिवासी युवतियों द्वारा ब्लॉक प्रिंट चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां तैयार की जा रही हैं। इनकी डिमांड ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे विकसित शहरों में बढ़ रही है। मध्यप्रदेश में मई-1990 से ग्रामोद्योग विभाग स्थापना के साथ ही ग्रामोद्योग के सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार अग्रसर है। हाथकरघा संचालनालय, रेशम संचालनालय के साथ-साथ संत रविदास मप्र हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, मध्यप्रदेश माटी कला बोर्ड के माध्यम से स्थानीय शिल्पियों का कौशल उन्नयन कर उनके उत्पादों को बाजार मुहैया कराए जा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल के बाद अब लोकल फॉर ग्लोबल बनाने के तर्ज पर प्रदेश के शिल्प और शिल्पकारों को नई पहचान दिलाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार का खादी-ग्रामोद्योग विभाग सक्रिय है। ग्रामोद्योग उत्पादों को ई-कामर्स प्लेटफार्म से जोड़ने के जो प्रयास किए जा रहे है, उससे हमारे कारीगरों के हौसलों और कला को नई उड़ान मिल सकी है। प्रदेश और देश में बेचे जाने वाले उत्पाद अब विदेशों में आसानी से पहुंच रहे हैं। प्रदेश के हाथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के ब्रॉण्ड मृगनयनी, खादी एवं ग्रामोद्योग के ब्रॉण्ड कबीरा एवं विंध्यवैली को प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफार्म अमेजॉन एवं फ्लिपकार्ट तथा रेशम वस्त्रों के ब्रॉण्ड प्राकृत को फ्लिपकार्ट से जोड़ा गया है। विंध्यवैली ब्रॉण्ड के अंतर्गत दैनिक उपयोग के साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, च्यवनप्राश, आंवला, मुरब्बा, जैम, सॉस, सैनेटाइजर, दाल, बेसन, आटा, दलिया जैसे प्रोडक्ट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार मुहैया हो रहा है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा मप्र हस्तशिल्प तथा हाथकरघा विकास निगम मृगनयनी प्रदेश और प्रदेश के बाहर एम्पोरियम और शो-रू के माध्यम से उत्पादों को बाजार मुहैया करा रहा है।

किसानों को 1.17 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान

बाढ़ में डूबी 778 हेक्टेयर में बाजरा और तिल की फसल

» 15 सौ से अधिक किसानों को मुआवजा देने की तैयारी में जुटा प्रशासन

» सिंध, चंबल, बेसली नदी में बाढ़ से 67 गांव बाढ़ की चपेट में आए थे

नीरज शर्मा, भिंड

अगस्त महीने के पहले सप्ताह में आई बाढ़ से 778 हेक्टेयर में बोयी गई बाजरा और तिल की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। प्रशासन की फायनल सर्वे रिपोर्ट में करीब 1 करोड़ 17 लाख 40 हजार रुपए से अधिक नुकसान होने का आंकलन किया गया है। वहीं प्रशासन अब 15 सौ से अधिक पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की तैयारी में जुटा हुआ है। गौरतलब है कि चार अगस्त को सिंध, चंबल और बेसली नदी में एक साथ आए उफान की वजह से करीब 67 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे। सबसे ज्यादा तबाही सिंध नदी ने मचाई। सिंध नदी किनारे के 33 गांवों में पानी ने सब कुछ तबाह कर दिया। बाढ़ का पानी जहां लोगों के घरों के साथ गृहस्थी का सामान अपने साथ बहा ले गया। वहीं खेतों में बोयी गई फसल को भी पूरी तरह से नष्ट कर गया। गांव से पानी उतरने के बाद से ही प्रशासन नुकसान का आंकलन करने के लिए सर्वे करा रहा था। फायनल रिपोर्ट में सामने आया कि जिले में 778 हेक्टेयर में बोयी गई बाजरा और तिल की फसल बाढ़ की वजह से बर्बाद हो गई, जिसमें 2 हेक्टेयर से अधिक वाले 112 किसानों की 128 हेक्टेयर जमीन है। जबकि दो हेक्टेयर से कम वाले 1500 किसानों की 650 हेक्टेयर जमीन है।

432 मकान हुए धराशायी

बाढ़ के पानी से 432 मकान पूर्ण रूप से धराशायी हो गई है। जबकि 3457 मकान क्षतिग्रस्त हैं, जिसमें 2564 पक्के मकान हैं। वहीं 893 कच्चे मकान है। सबसे ज्यादा नुकसान रौन तहसील में हुआ है। यहां 667 पक्के और 301 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं 236 मकान पूरी तरह से ढह गए हैं। हालांकि प्रशासन ने पूर्ण रूप से धराशायी हुए मकानों के मालिकों को राहत के तौर पर फिलहाल 6 हजार रुपए के मान से 403 लोगों को 24 लाख 18 हजार रुपए बांट दिए हैं। साथ ही इन लोगों को नया घर बनाने के लिए 95 हजार 100 रुपए और मजदूरी के 25 हजार रुपए भी दिए जाएंगे। इसके अलावा क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए 1838 परिवारों को 88.84 लाख रुपए प्रदाय कर दिए हैं।

खाते में पहुंचेगी मुआवजा राशि

प्रशासन ने बाढ़ के पानी से बर्बाद हुई फसल का सर्वे करा लिया है। अब किसानों को मुआवजा देने के लिए आरबीसी के प्रावधानों के तहत स्वीकृति पत्रक जारी कोषालय को भेजे जाएंगे, जिसके बाद शासन के ग्लोबल बजट से सीधे किसानों के खाते में उनके नुकसान की राशि पहुंचेगी। हालांकि किसानों का बाढ़ के पानी से सिर्फ उनकी बोयी गई फसल ही बर्बाद नहीं हुई है। बल्कि खेत भी खराब हो गए हैं, जिसे ठीक करने में भी काफी पैसा खर्च होगा।

इनका कहना है

बाढ़ से हुए नुकसान का लगभग फायनल सर्वे हो गया है। 778 हैक्टेयर भूमि बाजरा और तिल की बोयी हुई फसल खराब हुई है, जिससे करीब 1 करोड़ 17 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों को मुआवजा राशि देने की कार्रवाई की जा रही है।

डॉ. सतीश कुमार एस, कलेक्टर, भिंड

माधव नेशनल पार्क में फिर गूंजेगी टाइगर की दहाड़

खेमराज मौर्य, शिवपुरी

भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें बताया कि माधव नेशनल पार्क पिछले 200 वर्षों से बड़ी संख्या में टाइगर के रहवास के लिए जाना जाता है। इसलिए पार्क में टाइगर लाने की कवायद को जल्द अंजाम दिया जाए। सिंधिया ने बताया कि शिवपुरी का यह हिस्सा ग्वालियर रियासत के राज परिवार ने बसाया था। 1987 से 1996 तक यहां एक टाइगर यहां था, यह टाइगर बहुत तंदुरुस्त 8.5 फिट साइज का था।

1990 में माधव नेशनल पार्क में टाइगर सफारी का निर्माण भी किया गया, जिसमें उस समय 10-15 टाइगर थे। लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण धीरे धीरे यह सफारी बंद हो गई। और यहां जो टाइगर थे, वह विस्थापित कर दिए गए।

बाघों की बसाहट के लिए केंद्र सरकार का दल करेगा दौरा

छह करोड़ की योजना

सिंधिया ने वन मंत्री को बताया कि इसी माह माधव नेशनल पार्क के डायरेक्टर ने एक प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक वाइल्ड लाइफ को भेजकर माधव नेशनल पार्क में टाइगर की बसाहट और 5 वर्षीय कार्य योजना प्रस्तुत की है। जिसके लिए 106 करोड़ के बजट की भी मांग रखी गई है। सिंधिया के उक्त मांग के संदर्भ में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सकारात्मक पहल करते हुए अधिकारियों को निर्देश प्रदान कर दिए हैं, जल्दी ही केंद्र और प्रदेश सरकार का एक दल माधव नेशनल पार्क का दौरा करके उक्त विषय मे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। जिसके बाद टाइगर आने का रास्ता साफ हो जाएगा।

कैबिनेट का फैसलाः शुगर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर फोकस

किसानों को गन्ने के लिए हर क्विंटल पर 5 रुपए ज्यादा मिलेगा

संवाददाता, भोपाल/ नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने गन्ने का एफआरपी (फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस) पांच रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया। अब गन्ना किसानों को 290 रुपए प्रति क्विंटल का एफआरपी मिलेगा। लेकिन अगर किसी किसान की रिकवरी 9.5 प्रतिशत से कम होती है, तो भी उन्हें 275.50 रुपए प्रति क्विंटल जरूर मिलेंगे। केंद्र के इस निर्णय से मप्र के गन्ना उत्पादक किसानों को भी अच्छा लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और दतिया जिले हैं। मप्र के कुल गन्ना क्षेत्र का लगभग 65 प्रतिशत नरसिंहपुर जिले (लगभग 75000 हेक्टेयर) में है। इसे भारत के मध्य प्रदेश और हरियाणा की चीनी का कटोरा कहा जाता है। जिले में, 2500-3000 टीसीडी क्षमता वाली 09-10 चीनी मिलें हैं।

पांच करोड़ किसानों को होगा फायदा

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि देश के गन्ना किसानों ने उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करके रिकवरी बढ़ाई है। इससे पांच करोड़ गन्ना किसानों को फायदा होगा। चीनी मिलों और इससे जुड़े उद्यमों में लगभग पांच लाख वर्कर लगे हुए हैं। बढ़ी एफआरपी अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाले अगले मार्केटिंग सीजन के लिए है। गोयल ने बताया कि शुगर सीजन 2021-22 में गन्ने की उत्पादन लागत 155 रुपए प्रति टन रही है। इस तरह 290 रुपए प्रति क्विंटल का एफआरपी 10 प्रतिशत के रिकवरी रेट के हिसाब से प्रॉडक्शन कॉस्ट से 87.1 प्रतिशत ज्यादा है।

किसानों को होगी आमदनी

गन्ना किसानों को उनकी लागत पर आधे से ज्यादा रिटर्न दिलाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मौजूदा शुगर सीजन (2020-21) में चीनी मिलों ने 91,000 करोड़ रुपए से 2,976 लाख टन गन्ने की खरीदारी की है, जो ऑल टाइम हाई है। एमएसपी पर धान की खरीदारी के बाद इसकी खरीदारी सबसे ज्यादा हुई है। उनके मुताबिक शुगर सीजन 2021-22 में चीनी मिलें 3,088 लाख टन गन्ने की खरीदारी कर सकती है। इससे गन्ना किसानों को एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी होगी। गोयल ने बताया कि एफआरपी पिछले साल 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया था। उनके मुताबिक, गन्ने का मौजूदा एफआरपी अब तक के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है।

इनका कहना है

गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए चीनी सीजन 2021-22 के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 290 रुपए प्रति क्विंटल को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इससे किसानों के साथ ही चीनी मिल से जुड़े श्रमिक भी लाभान्वित होंगे। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य में वर्ष 2013-14 के मुकाबले वर्ष 2021-22 में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री

जबलपुरः पंचायत बंदरकोला की महिलाएं कमा रहीं एक लाख सलाना

एलोवेरा की खेती कर 12 महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर

संवाददाता, जबलपुर

गांव में महिलाओं की पहचान सिर्फ चूल्हा-चौका के लिए जानी जाती हैं। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण कस्बों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास तो बहुत हुए पर धरातल में परिणाम सामने में काफी समय लगा। इसी का नतीजा है कि जबलपुर जनपद की ग्राम पंचायत बंदरकोला की 12 महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। गरीबी के बोझ में दबे इन महिलाओं के घरों में कभी दीपावली-होली नहीं होती थी, परंतु अब हर रोज त्यौहार मनाए जा रहे हैं। इस गांव की महिलाएं एलोवेरा की खेती कर सलाना एक लाख रुपए कमा रही हैं। खास बात यह है कि इन महिलाओं की मदद से ग्राम पंचायत सरपंच ने 50 एकड़ में एक घना जंगल तैयार किया है। महिलाओं के इस कार्य की सराहना आसपास की पंचायतों में हो रही है। इनके कार्यों से प्रेरित होकर अन्य लोग भी इस कार्य में जुटने के लिए तैयार हो रहे हैं।

10 एकड़ में एलोवेरा की खेती

बंदरकोला ग्राम पंचायत के सरपंच अजय सिंह पटेल ने बताया कि गांव में कोई रोजगार नहीं है। पुरुष भी इतना नहीं कामाते हैं कि उनका घर ठीक ढंग से चल सके। इसी सब को ध्यान में रखकर पंचायत में खाली पड़ी 10 एकड़ शासकीय भूमि में एलोवेरा की खेती के लिए दुर्गा स्व-सहायता समूह नाम एक समूह बनाया गया जिसमें गांव की 12 महिलाओं को शामिल किया। महिलाओं को जिला पंचायत की तरफ एलोवेरा की खेती के लिए प्रशिक्षण दिया गया था।

चार साल से कर रहीं खेती

बंदरकोला ग्राम पंचायत की महिलाएं बीते चार ते साल से एलोवेरा की खेती कर रही हैं। हर छह माह में 50 हजार का एलोवेरा महिलाएं बेचती हैं। एक साल में एक लाख रुपए से ज्यादा का एलोवेरा बेच लेती हैं।

50 एकड़ में घना जंगल बसा

गांव की महिलाएं सिर्फ एलोवेरा की खेती तक सीमित नहीं रही हैं। उन्होंने पंचायत और शासन की योजनाओं पर हाथ बांटना शुरू कर दिया और 50 एकड़ में एक घना जंगल तैयार कर दिया। मनरेगा की 14 लाख की मदद से महिलाओं ने सरपंच के साथ मिलकर जंगल तैयार किया।

खास बातें

जिले में किसी भी ग्राम पंचायत के पास बंदरकोला पंचायत जैसा जंगल नहीं है। बंदरकोला को छोड़ अन्य किसी भी पंचायत में एलोवेरा की खेती नहीं हो रही है। जितना इस पंचायत की महिलाएं कमा रही हैं किसी और पंचायत या गांव की महिलाएं नहीं कमा रही हैं।

इनका कहना है

बंदरकोला ग्राम पंचायत की महिलाओं द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है। सभी जनपद अधिकारियों से कहा गया कि वह बंदरकोला ग्राम पंचायत से प्रेरणा लेकर पंचायतों में काम शुरू कराएं।

रितु बाफना, जिला पंचायत सीईओ, जबलपुर

» श्योपुर में भुगतान को लेकर अजीविका कंपनी और ठेकेदार में छिड़ गया विवाद

» ठेकेदार का आरोप काम कराने के बाद मजदूरी के 03 लाख रुपए नहीं दे रहे सीईओ

» सीईओ ने बाद में रुपए देने बचने के लिए थाने में दे दिया चोरी का झूठा आवेदन

महिला समूह के नाम पर की फसल खरीद में लाखों का घोटाला

संवाददाता, श्योपुर

महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर ग्रामीण आजीविका मिशन क्या गड़बड़झाला कर रहा है, इसकी बानगी इन दिनों महिलाओं के नाम पर हुई खरीदी फसल खरीदी का हिसाब है। महिलाओं के नाम पर खरीदे गए गेहूं और चने की मजदूरी हम्माल तुलावटियों को देने के बजाए अधिकारी खुद डकार गए। जब ठेकेदार ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की तो आजीविका मिशन के सीईओ अमित सिंह कुशवाह ने मजदूरी के रुपए ठेकेदार मो. अकील को देने की बात कहते हुए दो किस्तों में राशि अदा करने की बात कही, लेकिन एक किश्त देने के बाद सीईओ अमित ने खरीदा गया माल चोरी हो जाने की रिपोर्ट कराहल थाने में दर्ज कराने के लिए आवेदन देकर पल्ला झाड़ लिया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की उद्देश्य से इस बार शासकीय समर्थन मूल्य की खरीद महिला समूहों के माध्यम से कराई गई थी। हालांकि, अधिकतर केंद्रों पर महिला समूहों ने काम नहीं लिया।

कलेक्टर के पास पहुंची भ्रष्टाचार की शिकायत

कुछ केन्द्रों को एनआरएलएम अपने यहां पंजीकृत महिलाओं समूहों के माध्यम से खरीद केंद्र बनाए थे। इन केन्द्रों पर महिलाओं के बजाए एनआरएलएम के अधिकारियों ने ठेकेदारों के माध्यम से खरीद कराई थी। पूरी तरह पुरुष हाथों में होने के बावजूद यह खरीद महिलाओं के नाम पर दर्शाकर जहां पैसे की बंदरबांट कर ली। इसका खुलासा तब हुआ जब हम्माल और तुलावटियों को भुगतान नहीं होने पर ठेकेदार ने पैसे का तकादा करते हुए कलेक्टर से शिकायत की।

बैठक में स्वीकारा-पैसा दूंगा

कलेक्टर को शिकायत के बाद एनआरएलएम के डीपीएम डॉ. एसके मुदगल ने विभागीय जांच बैठा दी। जांच में शामिल विमल तिवारी, अनिल सक्सेना, रामराज मीणा ने जांच में नियम से खरीद होना और ठेकेदार को 03 लाख 50 हजार रुपए का भुगतान बकाया होना बताया था। इसकी तस्कीद खुद सीईओ अमित सिंह ने की। जांच दल के आगे अमित सिंह ने कैसे देना स्वीकारते हुए 50 हजार रुपए 27 जुलाई को एवं बाकी 03 लाख रुपए 27 अगस्त को देने की बात कही। इस बात का प्रमाणीकरण भी लिखा गया। 27 जुलाई को 50 हजार रुपए तो ठेकेदार को सीईओ द्वारा दे दिया गया, लेकिन जब 03 लाख रुपए देने की बात आई तो सीईओ अमित ने रुपए देने के बजाए कराहल थाने में आवेदन देकर खरीदी गई फसल चोरी हो जाने और चोरी के शक में ठेकेदार पर एफआईआर कराने की बात कही।

इनका कहना है

हमें ठेकेदार अकील को तीन लाख रुपए मजदूरी के देने हैं। यह पैसा नान से कमीशन मिलने पर देना था। बाढ़ की वजह से पैसा आने में देरी हुई है। जैसे ही पैसा आएगा हम उसे रुपए दे देंगे। जहां तक चोरी की बात है तो एक गाड़ी मिसिंग है, यह तो ऑनलाइन दिख रही है न ही किसी गोदाम पर। इसलिए मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई है। गाड़ी भरने की जिम्मेदारी ठेकेदार की थी, इसलिए पुलिस प्रोसेस में उससे पूछताछ कर रही है।

अमित सिंह कुशवाह, सीईओ, आजीविका मिशन

27 मई तक हुई खरीद में मैंने मजदूरों के माध्यम से मानपुर में चना की और कराहल में गेहूं की खरीद कराई थी। इसकी मजदूरी 06 लाख 80 हजार 210 रुपए बनी, लेकिन पैमेंट नहीं दिया गया। बाद में मेरे द्वारा कलेक्टर से शिकायत करने पर मुझे 3 लाख 80 हजार रुपए दे दिया, बाकी 03 लाख रुपए नहीं दिए हैं। मैं रोज दफ्तर के चक्कर लगा रहा हूं। सीईओ इस पैसे को खुद हड़प कर गया है और बचने के लिए झूठी एफआईआर कराना चाहता है।

मोहम्मद अकील, मजूदर ठेकेदार

» भारतीय वैज्ञानिकों ने एसएनपी आधारित इंडिगऊ चिप विकसित की

» चिप के मदद से देशी और संकर गायों को पहचानने में होगी आसानी

» गिर, साहीवाल जैसे 43 देशी गाय की नस्लों को संरक्षण की जरूरत

देशी गायों के संरक्षण और नस्ल सुधार में मदद करेगी 'इंडिगऊ' चिप

संवाददाता, भोपाल/नई दिल्ली

गिर, साहीवाल जैसी देशी नस्ल की गायों को पालने से पहले पशुपालकों को सोचना नहीं पड़ेगा कि गाय की शुद्ध है या कहीं संकर तो नहीं है। वैज्ञानिकों ने देशी गायों के संरक्षण के लिए एकल पॉलीमॉर्फिज्म (एसएनपी) आधारित इंडिगऊ चिप विकसित है, जिसकी मदद से देसी गायों की पहचान करना आसान हो जाएगा। पिछले कुछ सालों में एक बार फिर लोगों का रुझान देशी गायों की तरफ बढ़ा है, लेकिन इतने सालों में देशी और विदेशी गायों के संकर से नस्लें खराब भी हुई हैं। इससे परेशानी का हल निकालने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय पशु जैव प्रोद्योगिकी संस्थान (एनएआईबी), हैदराबाद के वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से यह स्वदेशी चिप विकसित की गई है। हाल ही में गिर, कंकरेज, साहीवाल, अंगोल आदि देशी पशुओं की नस्लों के शुद्ध किस्मों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत की पहली एकल पॉलीमॉर्फिज्म (एसएनपी) आधारित चिप इंडिगऊ का शुभारंभ किया गया है।

देशी गाय में गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक डॉ. सुबीर मजूमदार इंडिगऊ चिप के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि भारत में गाय की बहुत सारी देशी नस्लें हैं, जिनमें गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। जबकि विदेशी गायों के साथ ऐसा नहीं होता है। जरा सा तापमान बढ़ा की गाय बीमार हो जाती हैं। जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग है, दूसरे देश के लोग भी यही कहते हैं कि भारत कि गाय कैसे गर्मी बर्दाश्त कर लेती हैं। भारत में इतनी सारी दशी किस्में हैं। सब की कुछ न कुछ खासियतें हैं। कुछ अकाल यानी सूखे में भी रह लेती हैं। कुछ गर्मी में भी रह लेती हैं। गाय की जो भी खासियतें हैं वो उनके जीन में ही होती हैं।

मिलावट से हम खो रहे देशी गाय

डॉ. सुबीर मजूमदार ने कहा कि इन देशी नस्लों को हम खो रहे हैं, क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान से किसी दूसरी नस्ल का स्पर्म किसी दूसरी गाय में डाल दिया जाता है। विदेशी गायों के नस्ल के स्पर्म से भी गायों का कृत्रिम गर्भाधान किया गया, इसे क्या हुआ कि संकर किस्म पैदा हो गईं। लेकिन उनमें ढेर सारी खामियां हैं, जैसे कि वो गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं। जल्दी बीमार भी हो जाती हैं। ये खराब नस्लें किसानों के लिए बोझ भी बन जाती हैं, क्योंकि धीरे-धीरे गायों की नस्लें खराब होती जा रही हैं।

देश में 43 किस्म की गाय

देश में साहीवाल (पंजाब), हरियाणा (हरियाणा), गिर (गुजरात), लाल सिंधी (उत्तराखंड), मालवी (मालवा, मध्यप्रदेश), देवनी (मराठवाड़ा महाराष्ट्र), लाल कंधारी (बीड़, महाराष्ट्र) राठी (राजस्थान), नागौरी (राजस्थान), खिल्लारी (महाराष्ट्र), वेचुर (केरल), थारपरकर (राजस्थान), अंगोल (आंध्र प्रदेश), कांकरेज (गुजरात) जैसी 43 से अधिक देशी गाय की किस्में हैं।

मप्र में गाय को छोड़ देते हैं छुट्टा

साल 2019 में जारी 19वीं पशुगणना के अनुसार देश में गौवंशीय पशुओं की कुल संख्या 192.49 मिलियन है, जबकि मादा गायों की संख्या 145.12 मिलियन है। देश में विदेशी/संकर नस्लों की गौवंशीय पशुओं की संख्या 50.42 मिलियन और स्वदेशी//अवर्गीय की संख्या 142.11 मिलियन है। संकर किस्मों की वजह से दूध उत्पादन पर भी असर पड़ा है। धीरे-धीरे देशी नस्लें खराब हो गई हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में लोग गायों को छुट्टा छोड़ देते हैं, जो किसानों की फसलें बर्बाद करते हैं।

इनका कहना है

इंडिगऊ पूर्ण रूप से स्वदेशी और दुनिया की सबसे बड़ी पशु चिप है। इसमें 11,496 मार्कर हैं जो कि अमेरिका और ब्रिटेन की नस्लों के लिए रखे गए 777 के इलुमिना चिप की तुलना में बहुत ज्यादा हैं। हमारी अपनी देशी गायों के लिए तैयार किया गया यह चिप आत्मनिर्भर भारत की दिशा के लिए एक शानदार उदाहरण है। यह चिप बेहतर पात्रों के साथ हमारी अपनी नस्लों के संरक्षण के लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने में सहयोग प्रदान करने वाले सरकारी योजनाओं में व्यावहारिक रूप से उपयोगी साबित होगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री

केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान का शुभारंभ, बोले

किसानों और वैज्ञानिकों की ताकत से दुनिया में नंबर वन होगा भारत

सागर। गत दिवस भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किसानों के लिए खाद्य एवं पोषण विषय पर कृषि विज्ञान केंद्र, सागर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बर्चुअल किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि के क्षेत्र में भारत पूरे विश्व में प्रथम अथवा द्वितीय स्थान पर बना हुआ है। इस अवसर पर देश के कुल 722 कृषि विज्ञान केंद्र एवं उससे जुड़े हुए समस्त किसानों को कृषि की उन्नत तकनीकी को अपनाते हुऐ आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान में उन्होंने उच्च गुणवत्ता युक्त रसायन मुक्त पोषण तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का उपयोग करने की सलाह दी। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. केएस सादव के मार्गदर्शन में वैज्ञानिकद्वय डॉ. ममता सिंह, डॉ. वैशाली शर्मा ने 40 - 45 किसान एवं कृषक महिलाओं को विविध विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया। साथ ही केंद्र पर लगाई गई उन्नत किस्म प्रदर्शनी के साथ-साथ विभिन्न प्रदर्शन इकाइयों का भ्रमण कराया गया। किसानों को गेंदा बीज वितरण किया गया।

चुनौतियों पर करना होगा मंथन: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत ने खाद्यान्न के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हमारे किसानों व वैज्ञानिकों की इतनी ताकत है कि हम दुनिया में प्रतिस्पर्धा करें तो लगभग सभी जिंसों में नंबर एक हो सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उत्पादन व बढ़ती हुई उत्पादकता हम सब के लिए गौरव व प्रसन्नता का विषय है, लेकिन आजादी के 75वें वर्ष में हम ऐसे मुकाम पर खड़े हैं, जहां हमें आत्मावलोकन करने के साथ ही चुनौतियां और उनके समाधान पर विचार करना होगा।

किसान महंगी फसलें बोएं: तोमर ने कहा कि वर्षा आधारित व अन्य क्षेत्रों में खेती के स्वरूप, प्रकार व बीजों के ईजाद पर भाकृअनुप सफलतापूर्वक काम रही है। साथ ही यह भी प्रयत्न किया जा रहा है कि कृषि व किसान नई तकनीक से जुड़ें। उत्पादन महारत के साथ-साथ प्रचुरता को प्रबंधित करना भी अहम है। हमारे उत्पाद गुणवत्तापूर्ण हो, वैश्विक मानकों पर खरे उतरे, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, कम रकबे- कम सिंचाई में, पर्यावरण के मित्र रहते हुए पढ़े-लिखे युवा कृषि की ओर आकर्षित हो, यह सरकार के साथ किसानों की भी जिम्मेदारी है।

तब भारत होगा आत्मनिर्भर: मंत्री ने कहा कि केवीके से जुड़े किसान अन्य किसानों को उन्नत खेती के लिए प्रेरित करें। एफपीओ, एग्री इफ्रा फंड, परंपरागत खेती के अंतर्गत जैविक खेती का रकबा बढ़ाने सहित विभिन्न योजनाओं में सभी किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करें। इससे क्रमशः विकासखंड, जिला, राज्य और अंततः देश समृद्ध होगा व भारत आत्मनिर्भर बन सकेगा।

ओडीएफ गांव सुनिश्चित करने सरकार ने छेड़ा सुजलम अभियान

संवाददाता, भोपाल/ नई दिल्ली

जलशक्ति मंत्रालय ने मप्र सहित देशभर में अधिक से अधिक गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाने के लिए 100 दिनों के अभियान सुजलम की शुरुआत की। यह अभियान ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन, विशेष रूप से 10 लाख सोक-पिट के निर्माण और अन्य ग्रे वाटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से शुरू किया गया है। गांवों में या गांवों के बाहरी इलाकों में अपशिष्ट जल का निपटान और जलाशयों का बंद होना प्रमुख समस्याओं में से एक है। सुजलम अभियान अपशिष्ट जल के प्रबंधन में मदद करेगा जो बदले में जल निकायों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। अभियान का प्रयास कम समय में त्वरित तरीके से देशभर के गांवों के लिए ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल करने की दिशा में होगा। अभियान अगले 100 दिनों तक आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत जारी रहेगा।

ग्रामीण स्तर पर 10 लाख सोक-पिट का कराया गया निर्माण

जल प्रबंधन में मिलेगी मदद

यह अभियान न केवल गांवों में भूजल के प्रबंधन के लिए वांछित बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा, बल्कि जल निकायों के स्थायी प्रबंधन में भी मदद करेगा। इसके अलावा, यह पहल सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएमजी) चरण-2 गतिविधियों की गति को बढ़ावा देगी और ओडीएफ-प्लस गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी, दीर्घकालिक रखर-खाव और निर्मित बुनियादी ढांचे की स्थिरता सुनिश्चित करेगी। अभियान के तहत गांवों में आयोजित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं। वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने के लिए सामुदायिक परामर्श, खुली बैठक और ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करना।

हर घर में होगा शौचालय

ओडीएफ स्थिरता बनाए रखने और भूरे पानी के प्रबंधन के लिए वांछित संख्या में सोख-गड्ढों को प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित करें। स्थिरता और सोक-पिट निर्माण से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने के लिए 100-दिवसीय योजना विकसित करें। अन्य उपायों में आवश्यक संख्या में सोक-पिट का निर्माण, आईईसी और सामुदायिक जुटाव के माध्यम से आवश्यक शौचालयों को फिर से बनाना और गांव में सभी नए उभरते घरों में शौचालय की पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है।

» किसानों की तकदीर बदलने के लिए जवाहर प्रोजेक्ट लागू » जबलपुर के 38 गांवों के 615 किसानों का हुआ चयन

एक खेत में आठ फसल उगाएंगे किसान

संवाददाता, भोपाल/ जबलपुर

किसानों की आय दोगुनी करने की बात भले ही कपोल कल्पित लगे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अनूठी तकनीक तैयार की है। इससे किसान एक समय में एक खेत से आठ फसल एक साथ ले सकेंगे। इसका फायदा ये होगा कि कम जगह में किसान अधिक फसल का विकल्प अपना सकेंगे। कृषि विवि ने इस तकनीक को नाम दिया है जवाहर प्रोजेक्ट। जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि की पहल पर प्रदेश में जवाहर प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इसका प्रायोगिक परीक्षण जबलपुर जिले के किया जाएगा। किसानों का चयन और बीज नर्सरी का इंतजाम कर लिया गया है। प्रदेश में पहली बार ऐसा होगा, किसान एक साथ एक खेत 8 फसलों की पैदावार करेंगे। जबलपुर जिले में जवाहर प्रोजेक्ट सफल रहा तो अन्य जिलों में इसे लागू किया जाएगा।

प्रोजेक्ट पर एक नजर

जवाहर लाल नेहरू कृषि विवि और जिला पंचायत की संयुक्त पहल। 38 ग्रामों में शुरू होगी जवाहर प्रोजेक्ट की खेती, 615 किसानों का चयन। 41 हजार 900 पौधे नर्सरी र्स में तैयार हुए। बोरियों में मिट्टी भरकर एक खेत में अरहर, धनिया, हल्दी, बैगन, मिर्ची, टमाटर, भिंडी और अदरक की उपज लिया जाएगा।

इनका कहना है

आमतौर पर किसान एक सीजन में एक ही फसल प्राप्त करते हैं, लेकिन जवाहर प्रोजेक्ट में सहफसली पर जोर रहेगा। किसान ने यदि अरहर की बोवनी की है, तो वह उस खेत में हल्दी, धनिया, बैगन, मिर्ची, टमाटर, भिंडी और अदरक की फसल भी ले सकेंगे। जिले के 38 गांव के 615 किसानों का चयन किया गया है। इस प्रोजेक्ट से किसान आत्मनिर्भनर्भ बनेंगे और उनकी आय भी बढ़ेगी।

रिजु बाफना, सीईओ, जिला पंचायत, जबलपुर

जवाहर प्रोजेक्ट

प्रोजेक्ट के तहत जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि में पहले जिला पंचायत आजीविका मिशन के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद अधिकारियों ने ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों को प्रोजेक्ट के बारे में बताया। इसके तहत कृषि विवि में 8 फसलों की नर्सरी तैयार की गई है। इसको जिला पंचायत के अधिकारी किसानों को देंगे। प्रोजेक्ट से किसान आत्मनिर्भन बनेंगे और उनकी आय भी बढ़ेगी।

सामान्य खेती से अलग

आमतौर पर किसान एक सीजन में एक ही फसल प्राप्त करता था, लेकिन जवाहर प्रोजेक्ट में सहफसली पर जोर रहेगा। किसान ने यदि अरहर की बोवनी की है, तो वह उस खेत में हल्दी, धनिया, बैगन, मिर्ची, टमाटर, भिंडी और अदरक की फसल भी ले सकेगा। कोई एक फसल की बोवनी पूरे खेत में होगी और अन्य फसलों को बोरियों में मिट्टी भरकर की जाएगी।

बैतूलः 40 मिनट में दो एकड़ में कीटनाशक का छिड़काव किया गया

पहली बार सोयाबीन फसल पर ड्रोन से किया दवा का छिड़काव

संवाददाता, बैतूल

कीटनाशक छिड़काव तेजी से करने के लिए जिले में अब ड्रोन से फसलों पर कीटनाशक छिड़काव शुरू हो सकता है। इसके लिए बैतूल बाजार के कृषि विज्ञान केंद्र के पीछे प्रायोगिक तौर पर लगाई सोयाबीन फसल पर ड्रोन से फफूंदनाशक का छिड़काव करवाया। 40 मिनट में दो एकड़ सोयाबीन पर फंगसनाशक का छिड़काव किया। कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग और प्रयोग करता रहता है। किसानों को नई तकनीकों से परिचय दिलवाने और जिले के किसानों को उन्नति कृषि से जोड़ने के लिए ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव का प्रयोग कृषि विज्ञान केंद्र में किया गया। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र में ड्रोन से स्प्रे का प्रदर्शन आयोजित किया। इस कार्यक्रम में किसानों तथा कृषि अधिकारियों को ड्रोन के प्रयोग, उसकी तकनीकी दक्षता, प्रयोग करने की विधि एवं अन्य जानकारियां दीं। कार्यक्रम के दौरान केंद्र प्रमुख डॉ. वीके वर्मा, आरडी बारपेटे और डॉ. मेधा दुबे उपस्थित थीं। चेन्नई से आए गरुड़ एअरोस्पेस लिमिटेड के ड्रोन एक्सपर्ट ने इस दौरान ड्रोन उड़ाकर छिड़काव का प्रदर्शन किया।

सात लाख का आएगा एक ड्रोन

हालांकि ड्रोन से छिड़काव की इस विधि में काफी राशि खर्च करनी पड़ेगी। सात लाख की लागत से एक ड्रोन खरीदना पड़ेगा। इस डिमांस्ट्रेशन के बाद कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से अब प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। यदि मंजूरी मिलती है तो ड्रोन खरीदे जाएंगे।

फसल के हिसाब से करेंगे सेटिंग

फसल और कीटनाशक के प्रकार के हिसाब से अलग-अलग फसल की अलग-अलग सेटिंग कर ड्रोन को नीचे और ऊपर रखा जाएगा। जिससे कीटनाशक सही ढंग से छिड़का जा सकेगा। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय वर्मा ने बताया कि सामान्य ड्रोन से यह ड्रोन काफी बड़ा रहता है। इसमें कैमरा नहीं होता। इससे कीटनाशक, निंदानाशक, फफूंदनाशक, लिक्विड फर्टिलाइजर का छिड़काव करवाया।

ड्रोन की बैटरी जल्द होती है खराब

दावा किया जा रहा है कि ड्रोन से केवल 20 मिनट में एक एकड़ जमीन पर कीटनाशक छिड़का जा सकता है। हालांकि इसमें सबसे बड़ी परेशानी बैटरी की आती है। बताया जाता है कि बैटरी जल्द खराब होने और ज्यादा नहीं चलने के कारण बैटरी का खर्च ज्यादा आता है। गौरतलब है कि ड्रोन काफी महंगा होता है। किसान इसका रखरखाव करने में सक्षम नहीं होते। हालांकि ड्रोन छिड़काव से मजदूरी की राशि और समय की बचत जरूर होती है।

18 दिन बाद काम पर लौटे पटवारी

भोपाल। मध्यप्रदेश में पटवारियों की 18 दिन चली कलमबंद हड़ताल की वजह से आय-जाति, जमीन समेत रेवेन्यू से जुड़े 50 हजार से ज्यादा मामले पेंडिंग हो गए हैं। इन्हें पटवारी छुट्टी के 3 दिनों में भी काम करके निपटाएंगे। मप्र पटवारी संघ ने इस संबंध में प्रदेशभर के पटवारियों को मैसेज जारी किया है। सबसे पहले आय-जाति के सर्टिफिकेट और जमीन से जुड़े मामले निपटाए जाएंगे। इन्हें लेकर ही सबसे ज्यादा परेशानी हुई है। प्रदेश के 19 हजार पटवारी 10 अगस्त से हड़ताल पर थे। हड़ताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को समाप्त हो गई। शनिवार, रविवार व सोमवार को लगातार 3 दिन तक सरकारी छुट्टी है। इस कारण पेंडिंग मामलों को नहीं निपटाया जा सकता था। पटवारी संघ ने निर्णय लिया है, छुट्टी वाले दिन भी वे काम करेंगे।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **सतीश उपाध्याय, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)